छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन
तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय

// अधिसूचना //

कमांक/ F9-02/09/42 दिनांक 30-12/2009

विचारोपरांत छ.ग. शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा निजी तथा स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय में सी.जी. कोटा (CG Quota), ऑल इंडिया कोटा (AI Quota) एवं मेनेजमेंट कोटा (Mngt. Quota) में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है । साथ ही पूर्व निर्धारित ऑल इंडिया कोटा को समाप्त कर अन्य राज्य कोटा (OS Quota) में परिवर्तित किया जाता है अन्य राज्य कोटा केवल अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित रहेगा तथा छत्तीसगढ़ कोटा में केवल छ.ग. के मूल निवासी ही प्रवेश के पात्र होंगे ।

विवरण	वर्तमान कोटा			सत्र 2010-11 से कोटा		
	CG	AI	MGT	CG	OS	MGT
निजी संस्थायें	60	25	15	75	10	15
के.आई.टी., रायगढ़	80	20	NIL	90	10	NIL
आई. टी. कोरबा	60	25	15	75	10	15
शासकीय संस्थायें	100	–	–	100	–	–

सी.जी. कोटा की सीट को सी.जी.पी.ई.टी. की मेरिट से तथा अन्य राज्य कोटा को एआईईईई की मेरिट से तथा मेनेजमेंट कोटा को सी.जी.पी.ई.टी. अथवा एआईईईई की मेरिट से भरी जायेगी । यह अधिसूचना निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों पर भी लागू रहेगी । अल्पसंख्यक संस्था पर यह अधिसूचना लागू नहीं रहेगी । तथापि यह भी कि अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण अन्य राज्य कोटा (OS Quota) को सी.जी. कोटा में उसी प्रकार सी.जी. कोटा को अन्य राज्य कोटा में परिवर्तन किया जा सकता है । इसी प्रकार एम.सी.ए. तथा बी.फार्मेसी में भी उपरोक्तानुसार ही कोटा निर्धारित रहेगा तथा बी.ई./बी.फार्मेसी लेटरल एण्ट्री पाठ्यक्रम में भी यही कोटा निर्धारित रहेगा, यदि कोई संस्था मेनेजमेंट कोटा Surrender करना चाहती है तो उसे काउंसिलिंग प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व लिखित में इसकी सूचना देनी होगी, आंशिक Surrender मान्य नहीं होगा ।

सचिव
छ.ग. शासन
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पृ.कमांक/ रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, तकनीकी शिक्षा विभाग, बायरन बाजार, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. रजिस्ट्रार, छ.ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, नार्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर-8, भिलाई की ओर सूचनार्थ ।
3. अध्यक्ष, एपिक, आर.आई.टी. शहर कार्यालय, सी - 15, शैलेन्द्र नगर, बैंक ऑफ बड़ोदा ए.टी.एम. के सामने, रायपुर ।

सचिव
छ.ग. शासन
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग